

ग्रसाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II---लण्ड 3---उपलण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

rio 26]∶

नई बिल्ली, मंगलवार, जनवरी 20, 1970/पौष 30, 1891

No. 261

NEW DELHI, TUASDAY, JANUARY 20, 1970/PAUSA 30, 1891

इस भाग म भिन्न पृष्ठ सरवा दी जाती है जिससे कि यह ग्रलग संकलन के रूप म रका जा सके। Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

MINISTRY OF INDUSTRIAL DEVELOPMENT, INTERNAL TRADE AND COMPANY AFFAIRS

(Department of Industrial Development)

NOTIFICATION

New Delhi, the 20th January 1970

S.O. 235.—Whereas the Central Government has, as required by sub-section (2) of section 78C of the Indian Patents and Designs Act, 1911, reconsidered the question whether the direction issued under sub-section (1) of the said section to the Controller by the Notification of the Government of India, Ministry of Industrial Development, Internal Trade and Company Affairs (Department of Industrial Development) No. S.O. 1631, dated the 22nd April, 1969, as published in the Gazette of India, Part II, Section 3(ii), dated the 3rd May, 1969, continues to be necessary or expedient in the public interest;

And whereas on such reconsideration it appears to the Central Government that the said direction continues to be necessary in the public interest;

Now, therefore, in pursuance of sub-section (3) of the said section, the Central Government hereby notifies that the said direction continues to be necessary in the public interest.

[No. F. 31(3)-PP&D/68.]

K. J. GEORGE, Jt. Secy.

भौद्योगिक विकास, भाग्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्रालय

(श्रौद्योगिक विकास विभाग)

प्रधिसूचना

नई विल्ली, 20 जनवरी, 1970

सां० भां० 235:—यतः, केन्द्रीय सरकार ने, जैसा कि भारतीय पेटेन्ट तथा डिजाईन म्रधिनियम, 1911 के खण्ड 78 (ग) उप-खण्ड (2) के अनुसार आवश्यक है, इस प्रश्न पर कि उक्त खण्ड के उपखण्ड (1) के अन्तर्गत नियन्त्रक को भौद्योगिक विकास, आन्तरिको व्यापार तथा कम्पनी कार्य मंद्रालय (भौद्योगिक विकास विभाग) द्वारा सांविधिक आदेश, 1631 दिनांक 22 अप्रैल, 1969 को अधिसूचना द्वारा जारी किए गए निवेश को जो भारत के राजपन्न भाग (2) खण्ड 3(2) में दिनांक 3 मई, 1969 को प्रकाशित हुआ था आगे जारी रखा जाए इस पर पुनर्विचार किया और सरकार इसको जारी रखना जनहित में आवश्यक समझती है। और पुनर्विचार पर केन्द्रीय सरकार को ऐसा प्रतीत हुआ कि यह निवेश अनहित की दिन्ट से आवश्यक है।

म्रतः उक्त खण्ड के उप-खण्ड (3) के भ्रन्तर्गत केन्द्रीय सरकार यह श्रिधिसूचित करती है कि उक्त निर्देश जनहित में भ्रावश्यक हैं।

> [सं॰ फा॰ 31 (3) पी॰ पी॰ एण्ड डी॰/68] के॰ जे॰ जार्ज, संयुक्त सचिव।